प्रेस विज्ञप्ति

रायपुर, दिनांक 18 फरवरी, 2014

- शासकीय उच्च.मा. विद्यालय, लाहोद जिला-बलौदा बाजार केविद्यार्थियों ने विधानसभा की कार्यवाही का अवलोकन किया

-विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरीशंकर अग्रवाल से भेंट की

-शासकीय उच्च. मा. विद्यालय, लाहोद जिला-बलौदा बाजार के विद्यार्थियों एवं अध्यापकों ने आज विधानसभा की कार्यवाही का अवलोकन किया। कार्यवाही अवलोकन पश्चात् इन्होने विधानसभा परिसर स्थित समिति कक्ष में विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरीशंकर अग्रवाल से भेंट की। इस अवसर पर विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री देवेन्द्र वर्मा भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरीशंकर अग्रवाल ने कहा कि- विधानसभा प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत होती है एवं यहां जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि प्रदेश के हित तथा विकास के लिए योजनाएं बनाते हैं एवं सभा के प्रति शासन की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। स्थगन प्रस्ताव पर जानकारी देते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि- प्रदेश स्तर पर अविलंबनीय लोक महत्व का कोई ऐसा विषय हो जिस पर सभा की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराना आवश्यक हो तो विपक्ष के सदस्य उस विषय पर सभा में स्थगन प्रस्ताव ला सकते हैं। विषय की गंभीरता के आधार पर स्थगन की ग्राहाता पर अथवा स्थगन को सीधे स्वीकार कर उस पर चर्चा करायी जाती है। उन्होने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अनुसार होती है। बजट का महत्व बताते हुए विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरीशंकर अग्रवाल ने कहा कि-सभा में हर विभाग के बजट पर चर्चा होती है तथा बजट को बहुमत के आधार पर पारित किया जाता है। उन्होने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे देश के भावी नागरिक होने के नाते विधानसभा की कार्यवाही देखे एवं प्रदेश के विकास में अपनी भागीदारी

सुनिश्चित करें।

विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री देवेन्द्र वर्मा ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि- यदि विद्यार्थी एवं युवा विधानसभा की कार्यवाही देखें तो युवाओं का संसदीय व्यवस्था में विश्वास सुदृढ होगा। उन्होने कहा कि प्रश्नकाल ऐसा काल होता है जिसमे मान. मंत्रियों को भी सभा में मान. सदस्यों के प्रश्नों के मौखिक उत्तर देने होते हैं। प्रश्नकाल मान. मंत्रियों के लिए परीक्षा का काल होता है। बहुमत के बीच अल्पमत की आवाज दब न जाए इसलिए विधानसभा अध्यक्ष सभा में मान. सदस्य को बोलने का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं, जिससे मान. सदस्यों की भावनाएं सरकार के सामने प्रस्तुत हो सकें एवं शासन की जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।